**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्‍चतर शिक्षा विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 1657

उत्‍तर देने की तारीख: 27.12.2018

**शैक्षिक संस्थानों का मूल्यांकन**

**1657. श्री ए॰ विजयकुमारः**

 क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में शैक्षिक संस्थानों का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है;

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शैक्षिक संस्थानों को क्या-क्या लाभ दिए गए हैं;

(ग) क्या ऐसे संस्थानों का मूल्यांकन अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन मानक मानदंडों के अनुरूप नहीं है; और

(घ) क्या देश में शैक्षिक संस्थानों के मानकों को बढ़ाने के लिए कोई उपचारी उपाय किए गए हैं?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(डॉ. सत्‍य पाल सिंह)**

(क): उच्‍चतर शैक्षिक संस्‍थानों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्‍ता और उत्‍कृष्‍टता की पहचान करने और शैक्षिक गुणवत्‍ता बढ़ाने के लिए विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्‍चतर शैक्षिक संस्‍थानों का अनिवार्य मूल्‍यांकन और प्रत्‍यायन) विनियम, 2012 को अधिसूचित किया गया है। प्रत्‍यायन के उद्देश्‍य से 1994 में यूजीसी के एक स्‍वायत्‍त संस्‍थान के रूप में राष्‍ट्रीय मूल्‍यांकन और प्रत्‍यायन परिषद (एनएएसी) की स्‍थापना की गई है।

एनएएसी ने सात बिंदु अभिनिर्धारित हैं जिनमें प्रत्‍येक बिंदु नियत अधिमान के साथ मानदंड आधारित है, जो आईसीटी समर्थ पारदर्शी मूल्‍यांकन प्रक्रिया विधि के माध्‍यम से उच्‍चतर शिक्षा संस्‍थाओं के मूल्‍यांकन के लिए आधार के रूप में कार्य करते हैं।

(ख) से (घ): यूजीसी सम्‍पूर्ण विकास को कवर करने वाले विभिन्‍न पहलुओं नामत: पहुंच बढ़ाना, समानता सुनिश्चित करना, संगत शिक्षा प्रदान करने, गुणवत्‍ता और उत्‍कृष्‍टता सुधार करने, विश्‍वविद्यालय प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने, और अधिक संकाय सुधार कार्यक्रम प्रदान करने, छात्रों हेतु सुविधाएं बढ़ाने, शोध सुविधाओं को बढ़ाने और विश्‍वविद्यालय की अन्‍य योजनाओं हेतु प्रत्‍येक पात्र विश्‍वविद्यालय की सहायता करता है। यूजीसी पात्र कॉलेजों को उनके विकास हेतु अनुदान भी प्रदान करता है।

 उच्‍चतर शैक्षिक संस्‍थाओं में मानकों का सुधार करने और शैक्षिक और प्रचालन स्‍वायत्‍ता बढ़ावा देने के लिए अधिक आवश्‍यक प्रोत्‍साहन प्रदान करने के लिए, यूजीसी ने विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग (ग्रेडिड स्‍वायत्‍ता प्रदान करने हेतु विश्‍वविद्यालयों का श्रेणीकरण (केवल)) विनियम, 2018 और विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग (कॉलेजों को स्‍वायत्‍तता दर्जा देने और स्‍वायत्‍त कॉलेजों में मानकों के अनुरक्षण हेतु उपाय) विनियम, 2018 को अधिसूचित किया है।

 एचईआई को उच्‍चतर शिक्षा के वैश्‍विक मानकों के अनुकूल बनाने के लिए, यूजीसी ने उत्‍कृष्‍टता संस्‍थान (आईओई) योजना तैयार की है। यूजीसी ने उच्‍चतर शिक्षा के मानकों में सुधार करने के लिए गुणवत्‍ता अधिदेश जारी किया है।

 सरकार पहुंच, समानता और गुणवत्‍ता बढ़ाने के उद्देश्‍य से केंद्रीय प्रायोजित योजना नामत: राष्‍ट्रीय उच्‍चतर शिक्षा अभियान (रूसा) का भी कार्यान्‍वयन कर रही है। योजना का फोकस असेवित और अल्‍पसेवित क्षेत्रों का विकास करने पर है। योजना के तहत, अन्‍य बातों के साथ-साथ कॉलेजों और विश्‍वविद्यालयों को अवसंरचना अनुदान, विद्यमान कॉलेजों का मॉडल डिग्री कॉलेजों में उन्‍नयन आदि जैसे घटकों के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

**\*\*\*\*\***